



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502



16 फरवरी 2022

आरबीआई बुलेटिन - फरवरी 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी मासिक बुलेटिन का फरवरी 2022 का अंक जारी किया। बुलेटिन में 10 फरवरी, 2022 का मौद्रिक नीति वक्तव्य; एक भाषण; चार आलेख; और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

इसमें चार आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. जॉम्बीज और रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया; III. बैंड बैंक अच्छे बैंक के रूप में: भारत के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त अनुभव से सबक; और IV. भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थितियों ने वैश्विक विकास से अलग एक अलग मार्ग चुना है। तीसरी लहर से निकलने के साथ ही भारत की आर्थिक गतिविधियों में समुत्थान और कर्षण हो रहा है। मांग मानदंडों पर आशावाद और उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में वृद्धि के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों में विस्तार हो रहा है। जैसे-जैसे व्यवसाय एक नयी सामान्य स्थिति में लौटते हैं, नौकरी के परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है, यद्यपि ग्रामीण मांग में कमी के कुछ संकेत दिखाई दिये हैं। भले ही मौद्रिक नीति समायोजनकारी बनी हुई है, वैश्विक प्रभाव-विस्तार ने वित्तीय स्थितियों को नियंत्रित किया है।

II. जॉम्बीज और रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया

यह आलेख इस बात का परीक्षण करता है कि जॉम्बी फर्म (या लगातार घाटे में चल रही फर्म) भारत में प्रतिचक्रिय मौद्रिक नीति पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। यह ये भी पता लगाता है कि क्या मौद्रिक नीति आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान जॉम्बी फर्मों को ऋण प्रवाह आबंटित करके रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया में बाधा डालती है।

प्रमुख बिन्दु:

- जॉम्बी फर्मों में गैर-जॉम्बी की तुलना में अधिक लीवरेज पाया जाता है और गैर-जॉम्बी फर्मों की तुलना में जॉम्बी फर्मों की निधियों की औसत लागत मौद्रिक नीतिगत दर में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।
- अधिशेष चलनिधि की स्थिति के दौरान, हालांकि, गैर-जॉम्बी के ऋण प्रवाह की तुलना में जॉम्बी फर्मों के लिए प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहता है, जिसका अर्थ है कि विकास-समर्थक प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति रचनात्मक विनाश प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है।
- जॉम्बी फर्मों के लिए बैंकों से उधार लेने हेतु निवेश गतिविधि की संवेदनशीलता कम होने का अनुमान है, जो इंगित करता है कि वे नए निवेश करने की तुलना में उत्तरजीविता के लिए उधार संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे मार्जिन पर मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता कम होती है।

III. बैड बैंक अच्छे बैंक के रूप में: भारत के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त अनुभव से सबक

यह आलेख भारत में राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना का विश्लेषण विभिन्न देशों की प्रथाओं की पृष्ठभूमि में उन विशेषताओं को समझने के लिए करता है जिन्होंने उनकी सफलता में मदद की।

प्रमुख बिन्दु:

- दुनिया भर में साक्ष्य बताते हैं कि एक केंद्रीकृत बैड बैंक पर्याप्त तनाव कम करने में मदद कर सकता है और इसके विभिन्न प्रणालीगत लाभ हैं, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण प्रमुख परिचालन के लिए बैंकों के संसाधनों को मुक्त करना, निवेशकों और ग्राहकों को सकारात्मक संकेत देना, भारी छूट पर सामान की बिक्री से बचना और मौजूदा सार्वजनिक और निजी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की गतिविधियों को पूरक बनाना शामिल है।
- इन संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों में शामिल हैं कि नैतिक जोखिम को प्रोत्साहित किए बिना बैंकिंग तनाव को कैसे दूर किया जाए; सरकारी खजाने की लागत को कैसे कम किया जाए और एक ऐसा मूल्यांकन कैसे प्राप्त किया जाए जो अधिग्रहण करने वाली इकाई और विक्रेता, दोनों के लिए उचित हो।
- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया गया, पेपर बताता है कि भारत में एनएआरसीएल में कई अनुकूल डिजाइन और संरचना तत्व हैं। आगे बढ़ते हुए, निरंतर

राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता और परिचालन में पारदर्शिता प्रक्रिया को लागत और समय को प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

IV. भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव

चूंकि दूरदेशी सर्वेक्षण नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने इन सर्वेक्षणों का उपयोग महामारी के बाद के उद्यमों के दृष्टिकोण को गृहण करने के लिए किया है। यह आलेख 2019-21 के दौरान आयोजित त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) के माध्यम से महामारी के दौरान भारतीय निर्माताओं के रुख के विकास को समाहित करता है और विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित सुधार प्रक्रिया का अनुमान लगाता है।

प्रमुख बिन्दु:

- कोविड-19 महामारी की अचानक उछाल ने मांग की स्थिति में सुधार को धीमा कर दिया, जैसा कि उत्तरदाताओं की भावनाओं में परिलक्षित होता है।
- चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दिए जाने से मांग में तेजी देखी गई। पहली लहर के कम होने के बाद जब विनिर्माताओं के दृष्टिकोण ने देखना शुरू किया, तो महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर उनके रुख को धूमिल कर दिया। हालांकि, प्रभाव कम स्पष्ट था और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की बहाली के साथ स्थिति में तेजी से सुधार हुआ।
- सरकार द्वारा प्रदान की गई त्वरित क्षेत्र-विशिष्ट राहत, रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए सक्रिय मौद्रिक नीतिगत उपायों और तेजी से टीकाकरण के साथ निर्माताओं को निकट भविष्य में सुधार के बारे में आशावादी देखा जाता है।
- परिदृश्य विश्लेषण से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र अल्पावधि में अपनी कोविड-पूर्व प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकता है, हालांकि इसे अपने दीर्घकालिक प्रवृत्ति पथ पर लौटने में कुछ समय लग सकता है।